मध्यप्रदेश शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12/05/2016

क्रमांक एफ 10-16/2016/33 : राज्य शासन एतद् द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिये मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति - 2016 जारी करता है।

संलग्न - नीति

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हरिरंजन राव)
सचिव
म0प्र0 शासन पर्यटन विभाग

पृ.क्र. एफ 10-16/2016/33 भोपाल, दिनांक 12/05/2016

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विभाग।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. सचिव(समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

निरंतर पष्ठ.....2

12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. समस्त आयुक्त/कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
17. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल।
18. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख /पुस्तकालय।
19. अध्क्षत, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।

Bhutz
अवर सचिव
म0प्र0 शासन पर्यटन विभाग

मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016

MIDWAY TREAT

मिडवे ट्रीट
मार्ग सुविधा केन्द्र

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम

HIGHWAY TREAT DODI

The heart of
Incredible India

मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना एवं संचालन की नीति-2016

MIDWAY TREAT

मिडवे ट्रीट

मार्ग सुविधा केन्द्र

Tourist Info

अनुक्रमणिका

मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन की नीति 2016 — ***01***

The Policy For Establishment & Management of Way Side Amenities-2016 — ***09***

Lease Agreement (Brown Field Model) Way Side Amenities given for operation on lease to private investor — ***19***

मिडवे ट्रीट संचालन निर्देशिका — ***31***

The heart of
Incredible !ndia

मार्ग सुविधा केन्द्रों

की स्थापना एवं संचालन की नीति 2016

परिशिष्ट-1

मार्ग सुविधा केन्द्रों *(WAY SIDE AMENITIES)* की स्थापना एवं संचालन की नीति 2016

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन नीति में प्रदेश में संतुलित एवं समेकित पर्यटन की ऐसी अभिवृद्धि करना लक्षित है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो तथा मध्यप्रदेश समग्र पर्यटन अनुभव प्रदान करने वाला गन्तव्य बनें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना पर्यटन नीति की एक प्रमुख रणनीति है।

1. मार्ग सुविधा केन्द्रों की आवश्यकता

मध्यप्रदेश एक स्थलरूद्ध (Land Locked) प्रदेश है जिसकी सीमायें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से लगी हुई हैं। देश में पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले प्रमुख राजमार्ग प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ से गुजरते हैं, अतः आंतरिक एवं अंतर्राज्यीय परिवहन मुख्यतः सड़क मार्गों से होता है। मध्यप्रदेश के अंदर भी वृहद क्षेत्रफल होने से आवागमन में सड़क मार्ग से लम्बी दूरियां तय करना होती हैं। प्रदेश में राजमार्गों एवं ग्रामीण सड़कों का व्यापक नेटवर्क विद्यमान है जिस पर बड़ी संख्या में यात्री, व्यवसायी एवं पर्यटन निरंतर आवागमन करते हैं। पर्यटन की दृष्टि से विकसित देशों में पर्यटक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजमार्गों पर ''मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities)'' का जाल बिछाया गया है, जिसमें स्वच्छ शौचालय, खान पान, मूलभूत उपयोग की सामग्री, पेट्रोल पंप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में सड़क मार्गों पर पर्याप्त व्यवस्थित एवं स्तरीय यात्री सुविधा अधोसंरचना उपलब्ध नहीं हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि योजनाबद्ध रूप से स्तरीय मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना सुनियोजित रूप से नीति बनाकर की जाये ताकि यात्रियों को आवश्यक सुविधायें सुगमता से प्रत्येक 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा पर उपलब्ध हो जाये। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी समय-समय पर मार्ग सुविधा केन्द्रों (Way Side Amenities) की स्थापना हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रावधान किये गये हैं एवं राज्यों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी गयी है।

प्रदेश में स्थित पर्यटन केन्द्रों एवं टूरिस्ट सर्किट को जोड़ने वाले मार्गों पर यात्री सुविधाओं यथा स्वच्छ खान-पान, शौचालय, विश्राम, टेलिफोन एवं इंटरनेट, सुविधा स्टोर्स, प्राथमिक चिकित्सा, पार्किंग आदि की स्थापना से पर्यटन में वृद्धि होगी एवं स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे।

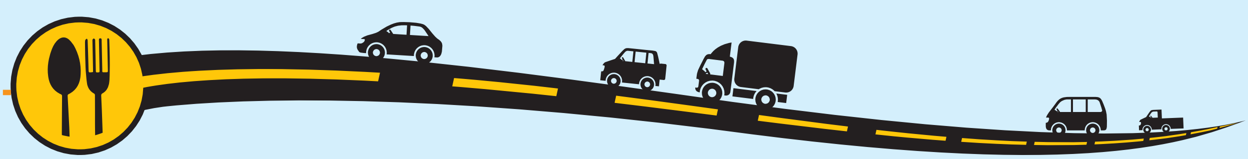

2. **रणनीति**

2.1 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा पूरे प्रदेश में रोड नेटवर्क एवं यात्री सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिये स्थल चिन्हित किये जायेंगे एवं मास्टर प्लान बनाया जायेगा।

2.2 तैयार मास्टर प्लान का विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों (Stake Holders) के मध्य प्रचार–प्रसार किया जायेगा ताकि निवेश का वातावरण तैयार हो। इन मार्ग सुविधा केन्द्रों की ब्राडिंग मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित ''लोगो'' एवं डिजाइन अनुसार की जायेगी।

2.3 मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु निम्नलिखित तीन मॉडल उपलब्ध होंगे :–

(i) **ब्राउन फील्ड मॉडल –**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार से विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त निधि से मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा मार्ग सुविधा केन्द्रों का निर्माण एवं निजी क्षेत्र द्वारा लीज पर लेकर संचालन।

(ii) **ग्रीन फील्ड मॉडल –**

पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध शासकीय भूमि पर निजी निवेशक द्वारा मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना एवं संचालन।

(iii) **फ्रेंचाइजी मॉडल –**

मास्टर प्लान में चिन्हित स्थलों के पास सामान्यतः दस किलोमीटर की परिधि में निजी निवेशक द्वारा निजी भूमि पर मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना अथवा उन्नयन एवं संचालन।

3. **विभिन्न मॉडलों में मार्ग सुविधा केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में दिशा– निर्देश**

3.1 **ब्राउन फील्ड मॉडल –**

3.1.1 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार निर्धारित डिजाइन एवं नियत सुविधाओं से पूर्ण मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना चिन्हित स्थल पर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा की जायेगी।

3.1.2 इस हेतु पर्यटन विभाग को भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

3.1.3 मार्ग सुविधा केन्द्र में कार/टूरिस्ट कोच/बस पार्किंग, फूड प्लाजा/रेस्टोरेंट, पुरूष एवं महिला टॉयलेट एवं वॉशरूम, चेंजिंग रूम, फर्स्ट–एड एवं 24X7 जल एवं विद्युत सुविधा निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा।

3.1.4 निर्मित मार्ग सुविधा केन्द्र पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी क्षेत्र को आवंटित की जाएगी।

3.1.5 निर्मित मार्ग सुविधाएँ अधिकतम 2 हेक्टेयर आनुषांगिक (appurtenant) भूमि सहित 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दी जाएगी। उपरोक्त अवधि के बाद भवन एवं भूमि का निराकरण तत्समय प्रचलित नीति/नियम अनुसार किया जायेगा।

3.1.6 निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य (अप–सेट प्राइज) रूपये दस लाख रखा जायेगा। निविदा में प्राप्त अधिकतम मूल्य भूमि का प्रीमियम होगा तथा इस प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष लीज रेंट के रूप में देय होगा।

3.1.7 निविदा आमंत्रण सूचना एक राष्ट्रीय तथा दो प्रादेशिक समाचार पत्रों में तथा निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

3.1.8 निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मार्ग सुविधा के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने से पूर्व इकाई एवं आनुषांगिक भूमि का विधिवत सीमांकन करवाया जाये एवं बाउंड्री का निर्धारण कर लिया जाये तथा इकाई तक विद्युत एवं जल प्रदाय तथा पार्किंग एवं आंतरिक मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो तथा कार्य योजनानुसार पूर्ण कर लिया गया हो।

3.1.9 पार्किंग एवं यात्रियों के लिये आवागमन हेतु आवश्यक भूमि छोड़कर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर निविदाकर्ता को निम्नानुसार गतिविधियों हेतु अधोसंरचना विकसित किये जाने की पात्रता रहेगी :-

A. **केवल सूचना देकर निमार्ण योग्य अधोसंरचनाएँ** :-

(I) चिल्ड्रन प्ले एरिया

(II) टेलिफोन/इंटरनेट कियोस्क

(III) सोवेनियर/हेंडिक्राफ्ट शॉप

(IV) बेबी/हेंडीकेप केयर रूम/सुविधाएँ

(V) फास्ट फूड आउटलेट/आइस्क्रीम पार्लर

(VI) मिनी जनरल स्टोर

(VII) वाहन मरम्मत केन्द्र/कार वॉशिंग सुविधा

(VIII) ट्रेवल डेस्क

(IX) फ्लॉवर शॉप/बुक्स-न्यूजपेपर आउटलेट

(X) लाइव आर्ट/हेंडिक्राफ्ट डिस्प्ले

(XI) अन्य आनुषांगिक गतिविधियाँ जो प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित की जाएँ।

B. **पूर्व अनुमति प्राप्त कर निर्माण योग्य अधोसंरचनाएँ** :-

(I) पेट्रोल पंप

(II) मैरिज गार्डन

(III) आवासीय कक्ष

(IV) बैंक ए.टी.एम.

(V) अन्य आनुषांगिक अधोसंरचनाएँ जो प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित की जायें।

3.1.10 उपरोक्त कंडिका 3.1.9(B) अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों हेतु पूर्वानुमति एवं निर्माण योजना का अनुमोदन प्रबंध संचालक से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3.1.11 ऐसी निर्मित अतिरिक्त अधोसंरचना, संचालन हेतु किसी अन्य व्यक्ति/इकाई को देने की स्थिति में संचालन हेतु दी गई अवधि मूल लीज अवधि नहीं होगी तथा लीज अवधि समाप्त होने पर संचालन हेतु दी गई अवधि स्वत: समाप्त मानी जायेगी।

3.1.12 लीज समाप्त होने के उपरांत निर्मित सभी अधोसंरचनायें स्वमेव पर्यटन विभाग के स्वामित्व में मानी जायेगी एवं इसके लिये संचालक को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

3.1.13 मार्ग सुविधा केन्द्र में तंबाकू युक्त पदार्थो यथा सभी पान मसालों, गुटखों, पान, सिगरेट, बीड़ी, पटाखे आदि विस्फोटक पदार्थ की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।

3.2 ग्रीन फील्ड मॉडल

3.2.1 मास्टर प्लान के अंतर्गत चिन्हित स्थलों पर मार्ग सुविधा केन्द्र हेतु शासन से पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित की जायेगी तथा इसे 30 वर्ष की लीज पर निजी निवेशकों को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

3.2.2 मार्ग सुविधा केन्द्र निर्माण हेतु अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि निर्धारित होगी, जिसका न्यूनतम आरक्षित मूल्य रुपये पाँच लाख होगा।

3.2.3 निविदा में प्राप्त अधिकतम मूल्य भूमि का प्रीमियम होगा तथा इस प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत प्रति वर्ष लीज रेंट के रुप में देय होगा।

3.2.4 निविदा आमंत्रण सूचना एक राष्ट्रीय तथा दो प्रादेशिक समाचार पत्रों में तथा निगम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी।

3.2.5 निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मार्ग सुविधा केन्द्र के लिये निविदा आमंत्रित किये जाने से पूर्व भूमि का विधिवत सीमांकन करवाया जाये एवं ब्राउंड्री का निर्धारण कर लिया जाये।

3.2.6 मार्ग सुविधा केन्द्र में कार/टूरिस्ट कोच/बस पार्किंग, फूड प्लाज़ा/रेस्टोरेंट, पुरुष एवं महिला टॉयलेट एवं वॉशरुम, चेंजिंग रुम, फर्स्ट–एड एवं 24X7 जल एवं विद्युत सुविधा निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस हेतु निर्माण योजना प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम से पूर्वानुमोदित करानी होगी।

3.2.7 उपरोक्त के अलावा अन्य सुविधाओं का निर्माण नीति की कण्डिका 3.1.9 से 3.1.13 के अनुसार किया जा सकेगा।

3.2.8 सफल निविदाकार को भूमि के आधिपत्य दिनांक से एक वर्ष की अवधि में मार्ग सुविधा केन्द्र निर्मित कर संचालन प्रारंभ करना होगा तथापि उठाये गये प्रभावी क़दमों एवं किये गये निर्माण कार्य के दृष्टिगत परिस्थितिजन्य कारणों से अधिकतम दो बार छः–छः माह की अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

3.2.9 मार्ग सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि ''जहाँ है जैसी है'' की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्माण एवं संचालन के लिये आवश्यक अनुमतियां/पंजीयन/लाइसेंस आदि प्राप्त करना एवं प्रचलित अधिनियमों/नियमों/शासन के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन करना चयनित निविदाकार का दायित्व होगा।

3.3 फ्रैंचाइजी मॉडल

3.3.1 मार्ग सुविधा केन्द्रों के मास्टर प्लान अनुसार चिन्हित स्थलों के 10 किलोमीटर के दायरे में निजी निवेशकों द्वारा निजी भूमि पर अपने व्यय से पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित यात्री सुविधाओं को मार्ग सुविधा केन्द्र के रुप में चिन्हित कर मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के फ्रैंचाइजी आधार पर संचालन की अनुमति दी जा सकेगी।

3.3.2 यह आवश्यक होगा कि ऐसी सुविधाएं नगर पालिका/नगर निगम की सीमा से बाहर संचालित/प्रस्तावित हों।

3.3.3 फ्रैंचाइजी प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार यात्री सुविधा अधोसंरचना का निर्माण एवं संचालन किया जाये। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा फ्रैंचाइजी हेतु ''लोगो '', ब्रांडिंग एवं अन्य गुणवत्ता के मापदण्ड उपलब्ध कराये जाऐंगे।

3.3.4 फ्रैंचाइजी प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा समय–समय पर विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

3.3.5 निर्धारित मापदंडों पर उपयुक्त पाई जाने वाली इकाई को रुपये एक लाख, फ्रैंचाइजी पंजीयन शुल्क देय होगा जो वापसी योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ₹**25000**/– फ्रैंचाइजी नवीनीकरण शुल्क देय होगा, जिसमें प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

3.3.6 सामान्यत: फ्रैंचाइजी, निर्धारित मापदंडों पर चयनित इकाई को ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' आधार पर दिया जायेगा। किन्तु एक से अधिक इकाई द्वारा आवेदन करने की दशा में फ्रैंचाइजी नवीनीकरण शुल्क की निर्धारित राशि से अधिक राशि के सीमित ऑफ़र सीलबंद लिफाफे में संबंधित आवेदकों से प्राप्त किये जायेंगे एवं अधिकतम राशि ऑफरकर्ता को फ्रैंचाइजी दी जायेगी।

3.3.7 ब्रॉउन फील्ड एवं ग्रीन फील्ड मॉडल हेतु नीति में वर्णित प्रतिबंधित गतिविधियां फ्रैंचाइजी इकाई के लिये भी प्रतिबंधित होंगी।

3.3.8 फ्रैंचाइजी इकाईयों के संचालन का निरीक्षण मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम अथवा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा नियत एजेंसी द्वारा समय–समय पर (6 माह में कम से कम एक बार आवश्यक रुप से) किया जायेगा एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

3.3.9 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार संचालन करना न पाया जाने पर फ्रैंचाइजी को त्रुटि सुधार हेतु एक माह का अवसर प्रदान किया जायेगा। तीन से अधिक बार मापदंडों का उल्लंघन पाये जाने पर फ्रैंचाइजी का पंजीयन रद्द किया जा सकेगा।

4. मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के दायित्व एवं अधिकार

4.1 निगम द्वारा ब्रांडिंग हेतु लोगो, विज्ञापन सामग्री एवं डिज़ाइन निर्धारित कर मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक को उपलब्ध करायी जायेगी।

4.2 निगम द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु निर्मित की जाने वाली सामग्री एवं सड़क पर लगाये जाने वाले बोर्ड/डिस्प्ले/होर्डिंग आदि पर ऐसी इकाई को विज्ञापित किया जायेगा तथा मार्केटिंग हेतु होने वाले आयोजनों में आमंत्रित किया जायेगा।

4.3 निगम द्वारा इकाई के दोनों ओर के पहुँच मार्ग पर 1000/500/100 मीटर पर इकाई के बारे में जानकारी हेतु प्रथम बार सूचना फलक (साइनेजेस) निर्धारित ब्राण्डिंग कर लगाये जायेंगे। इन सूचना फलकों के संधारण का दायित्व इकाई का होगा।

4.4 निगम द्वारा इकाईयों के निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधोसंरचना निर्माण एवं संचालन को सुनिश्चित किया जायेगा एवं लगातार अवहेलना पर फ्रैंचाइची अनुबंध के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4.5 निगम द्वारा इकाईयों को सूचारु संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा तथा यथा आवश्यकता कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

4.6 निगम को मार्ग सुविधा केन्द्रों के निर्माण, संचालन एवं फ्रैंचाइजी देने हेतु आवश्यक आवेदन पत्र, चैक लिस्ट, निरीक्षण प्रतिवेदन, पालन प्रतिवेदन व अन्य आवश्यक प्रारुपों को निर्धारित करने एवं लागू करने हेतु अधिकार होंगे।

4.7 निगम को इस नीति के प्रावधानों के अनुरुप लीज, लाइसेंस, निविदा प्रपत्र, आरएफपी व अन्य आवश्यक दस्तावेज निर्धारित करने, शुल्क निर्धारित करने/योग्यता निर्धारित करने एवं लागू करने के अधिकार होगे।

4.8 निगम को नीति के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होने वाले प्रीमियम, लीज रेंट, लाइसेंस फीस, फ्रैंचाइजी फीस, पंजीयन शुल्क व अन्य राशियों को प्राप्त करने, निगम खाते में जमा करने एवं मार्ग सुविधा केन्द्र तथा अन्य स्थानीय पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं संचालन हेतु व्यय करने के अधिकार होंगे।

4.9 अन्य प्रशासकीय अधिकार जो कि मार्ग सुविधा केन्द्रों के इस नीति के प्रावधानों के अनुसार विकास, संचालन, संधारण, प्रबंधन एवं नियमन हेतु प्रबंध संचालक द्वारा आवश्यक समझ जायें।

5. मार्ग सुविधा केन्द्र संचालक/फ्रैंचाइजी के दायित्व एवं अधिकार

5.1 पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधोसंरचना निर्माण एवं संचालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निगम द्वारा दिये गये सुझावों/ मार्गदर्शन पर अमल किया जायेगा।

5.2 निगम को देय राशियों का समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5.3 अधोसंरचना निर्माण एवं गतिविधि संचालन हेतु आवश्यक अनुमति/पंजीयन/लाइसेंस प्राप्त किये जायेंगे।

5.4 यात्रियों एवं पर्यटकों से मित्रवत व्यवहार किया जायेगा तथा उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

5.5 यात्री/पर्यटक शिकायत को सुनने एवं उसके तत्काल निकारण की व्यवस्था स्थापित की जायेगी तथा इसे स्थल पर विज्ञापित किया जायेगा।

5.6 मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ निष्पादित लीज अनुबंध, फ्रैंचाइजी अनुबंध आदि की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.7 इकाई को निगम द्वारा नियत लोगो, डिजाइन एवं प्रचार विषय वस्तु के अपनी मार्केटिंग हेतु उपयोग की अनुमति होगी तथा इसके अलावा अन्य लोगो, डिज़ाइन आदि उपयोग में नहीं लिया जायेगा।

5.8 इकाई द्वारा मार्ग सुविधा केन्द्र के निर्माण, संधारण एवं संचालन हेतु निगम की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा एवं इस संबंध में समस्या निराकरण/समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।

6. विविध

6.1 नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अधिकृत होंगे।

6.2 इस नीति के अंतर्गत लीज पर उपलब्ध करायी गई भूमि एवं भवन से प्राप्त प्रीमियम एवं लीज रेंट की राशि फ्रैंचाइजी पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क की राशि, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में ही जमा करते हुए, उक्त राशि का उपयोग मार्ग सुविधा केन्द्र तथा अन्य स्थानीय पर्यटन सुविधाओं के अधोसंरचना विकास एवं संचालन में व्यय करने की अनुमति होगी।

6.3 मार्ग सुविधा केन्द्रों के संचालन, संधारण, प्रबंधन एवं नियमन के संबंध में निगम एवं इकाई/संचालक/फ्रैंचाइजी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में निराकरण हेतु प्रमुख सचिव पर्यटन, मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

6.4 नीति के अंतर्गत जारी किए जाने वाले निविदा दस्तावेज, लीज अनुबंध, फ्रैंचाइजी अनुबंध दस्तावेज़ों के प्रारुप अनुमोदन हेतु पर्यटन विभाग, मध्यप्रदेश शासन अधिकृत होगा।

6.5 इस नीति के प्रावधानों की व्याख्या, मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण एवं आवश्यक संशोधन के लिए पर्यटन नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अधिकृत होगी।

मध्यप्रदेश पर्यटन
हाईवे ट्रीट

MADHYA PRADESH
The heart of Incredible !ndia

The Policy For Establishment & Management of Way Side Amenities-2016

The Policy For Establishment & Management of Way Side Amenities-2016

The Madhya Pradesh Tourism Policy aims to promote balanced and sustainable tourism which enables socio-economic development and to establish Madhya Pradesh as a destination which provides a complete tourist experience destination. Promoting private sector investment is one of the main strategies adopted in Tourism policy to achieve this aim.

1. NEED FOR WAY SIDE AMENITIES:

Madhya Pradesh is a land locked state with it's boundaries touching those of Mahrashtra, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh and Chhattisgarh. The main highways of the country running from east to west and from north to south run across the state due to its geographical position. Therefore, inter-state and inland traffic relying mainly on roads passes through here. Within Madhya Pradesh too, due to the large area of land one has to travel long distances by roads. There is a large network of highways and rural roads in state whereby large number of tourists, businessmen and other travellers commute.

Countries with developed tourism sector have networks of wayside amenities where availability of clean toilets, food & beverage, essential personal commodities and provision for refuelling is ensured. In state of Madhya Pradesh there is no standard and efficiently managed infrastructure available presently for the travellers. Considering this fact, it is essential to establish standard Wayside Amenities in a planned way by making a policy for it, so that the travellers may get essential facilities at every 40-50 kms distance. Ministry of Tourism, Government of India too have provided for establishing Wayside Amenities (hereinafter mentioned as "WSA") in many of their schemes and have also provided for financial assistance to states from time to time. Establishment of facilities for travellers such as food and beverage with clean toilets, resting place, telephone and internet, commodity-store, first aid, parking etc. on the routes connecting tourist centers will promote tourism and will provide employment to local people.

2. STRATEGY:

2.1 Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation shall, considering the needs of facilities for travellers, identify spots for establishment of Way Side Amenities and shall prepare a master plan.

2.2 The master plan so prepared shall be marketed and circulated among the stake-holders to create conducive atmosphere for investment.

2.3 The branding of the Way Side Amenities shall be done by the corporation via approved design and logo. Way Side Amenities shall be developed through the following three models -

(i) **Brown Field Model-** Way Side Amenity will be built under budget received under different schemes of Government of India and State Government. These will be then leased out to private sector for operating them.

(ii) **Green Field Model-** Way Side Amenity on government land available with the tourism department shall be built and operated by private investors.

(iii) **Franchisee Model-** Way Side Amenity built and operated on private land within a perimeter of 10 kms from the spots identified in Master Plan can be recognised in this model.

3. GUIDELINES FOR ESTABLISHING AND MANAGEMENT OF WAY SIDE AMENITIES UNDER DIFFERENT MODELS:-

3.1 Brown field Model-

3.1.1 The Corporation shall, at the identified places, establish Way Side Amenities with facilities enumerated by Ministry of Tourism, Government of India according to guidelines issued by them.

3.1.2 The State Government shall allot the land to Tourism Department.

3.1.3 It will be an essential requirement to construct car/tourist coach/bus parking, food plaza/restaurant, gents and ladies toilets and wash room, changing room, and provide for 24 x 7- water and electricity services.

3.1.4. The WSA, so constructed shall be allotted to private sector by means of a transparent tender process.

3.1.5 The WSA with a maximum land area of two hectares (appurtenant) shall be leased out for 30 years period. After this period the decision regarding land and building shall be taken according to the rules /policy in force at the time.

3.1.6 The minimum upset price of the tender shall be ₹10.00 lakhs (rupees ten lakhs). The highest price received by tender shall be premium of land and 1% (one percent) of the premium amount shall be the annual lease rent payable every year.

3.1.7 The notice inviting tender shall be published in national and state news papers and shall also be uploaded on the website of Corporation.

3.1.8 The Corporation shall ensure that prior to issuing of notice inviting tenders, the unit and the appurtenant land is measured and ear marked properly, boundaries are ascertained, electricity & water supply, place for parking and approach road is made available.

3.1.9 If any extra land, excluding the area for parking and way for travellers, is available, the bidder shall be eligible to develop infrastructure for following activities:-

A. INFRASTRUCTURES FOR WHICH ONLY INTIMATION SHALL BE SUFFICIENT:-

(i) Children play area

(ii) Telephone/internet kiosk

(iii) Souvenir/handicraft shop

(iv) Baby/handicapped persons care room/facilities

(v) Fast food outlets/Ice-cream parlour

(vi) Mini provision(General) store

(vii) Vehicle repair centre/car washing facility

(viii) Travel Desk

(ix) Flower shop/Books-News paper outlet

(x) Live-Art/handicraft display

(xi) Other relevant activities as decided by Managing Director, Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation.

B. INFRASTRUCTURES FOR WHICH PRIOR PERMISSION SHALL BE ESSENTIAL BEFORE THE CONSTRUCTION:

(i) Petrol Pump

(ii) Marriage Garden

(iii) Residential campus/rooms

(iv) Bank ATM

(V) Other relevant infrastructures as are decided by Managing Director, Madhya Pradesh Tourism Development Corporation.

3.1.10 Prior permission and approval of construction plan by Managing Director of the Corporation shall be mandatory for infrastructure to be constructed for activities mentioned in aforesaid clause 3.1.9(B).

3.1.11 The additional infrastructure so constructed, if handed-over to some other person /unit to run/manage, such handing-over shall stand terminated on expiry of lease period.

3.1.12 On the expiry date of lease all the infrastructures shall suo-moto come into control of Tourism Department, Government of Madhya Pradesh continuing its exclusive ownership. No compensation shall be payable for it.

3.1.13 Sale of all the material containing tobacco, such as all kinds of Pan-masala, Gutkha, Pan, Cigarettes & Bidi etc and all kinds of explosive and crackers etc shall be completely prohibited at WSA.

3.2. GREEN FIELD MODEL:

3.2.1 The land identified in master-plan (for WSA) shall be transferred to Department of Tourism by State Government and shall be leased out for a period of 30 years by means of transparent tender process to private sector investors.

3.2.2 A maximum of two hectares of land shall be fixed for WSA with minimum upset price of Rs. 5.00 lakhs (rupees five lakhs).

3.2.3 The highest price received through tender above the upset price shall be the premium of land and 1% (one percent) of this premium amount shall be the annual lease rent payable.

3.2.4 The notice inviting tender shall be published in one national and two state news papers and will also be uploaded on Website of the Corporation.

3.2.5 The Corporation shall ensure that prior to inviting tender for WSAs, the land is properly measured, ear marked and boundaries are ascertained.

3.2.6 It shall be essential to provide for car/tourist coach/bus parking, food plaza/restaurant, ladies and gents toilets, wash-room, changing-room, first aid facility and 24 x 7 electricity and water services at WSA and construction plan for these will need to be approved prior to construction.

3.2.7 Other facilities at WSA may also be constructed, subject to the instructions mentioned in clauses 3.1.9 to 3.1.13.

3.2.8 The successful bidder shall build and operate WSA within one year from the date of possession of the land. If despite effective initiatives the type of construction requires an extension, it will be considered upto a period of maximum 6 months. Only two such extentions will be permissible.

3.2.9 The land for construction of WSA shall be made available on "AS IS, WHERE IS" basis and it will be the duty of successful bidder to obtain all the necessary permissions/registration /licenses etc. and to comply with and abide by all prevailing laws, rules, orders, instructions & guidelines of Government.

3.3 THE FRANCHISEE MODEL:

3.3.1 Private investors will be allowed to operate WSA recognised by the Corporation on private land be it built/under construction / proposed if such WSA falls within ten kilometer perimeter of spots identified in the master plan.

3.3.2 It is essential that such franchisee facilities are run/are proposed to be run out side Municipal boundaries of any town/city.

3.3.3 It shall be mandatory to get a franchisee license that construction and management of travellers facilities is carried out as per the standard norms fixed by M.P. Tourism Development Corporation. The Corporation shall make "LOGO", "BRANDING" and other quality standards conditions available to franchisee.

3.3.4 M.P. Tourism Development Corporation shall from time to time advertise for inviting franchisee applications.

3.3.5 The unit found eligible as per the criteria fixed, shall pay rupees one lakh (₹1,00,000/-only) non-refundable franchisee registration fee. In addition to it an annual franchisee renewal fee of rupees twenty five thousand ₹25,000/- shall be payable. Franchisee renewal fee shall be increased by ten percent (10%) every year.

3.3.6 Normally the franchisee shall be granted on "first come, first get" basis from among the units found eligible as per the criteria. However, where more than one unit will apply, offers exceeding the amount fixed as annually paid renewable franchisee fee shall be received from applicants in sealed covers and franchisee will be awarded to the applicant rendering the highest offer.

3.3.7 Activities prohibited for brown field and green field models shall be strictly prohibited for franchisee unit too.

3.3.8 Management/operation of franchisee units shall be inspected once in every six months period by the Corporation or by an agency appointed by them and the inspection report shall be submitted to the Managing Director of the Corporation.

3.3.9 If by such inspection, it is found that the franchisee unit is not being strictly run/managed according to the standard norms fixed for it a one month notice shall be served to rectify the short-comings. However, if fixed standard norms are breached for more than three times registration of franchisee shall be cancelled.

4. DUTIES AND POWERS OF MADHYA PRADESH STATE TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION:

4.1 For the purpose of 'branding', the Corporation shall provide logo, advertisement material and design to the Franchisee holder.

4.2 Such franchisee units shall be given marketing support by putting up hoardings/display boards on roads and by giving them a presence on adverstisement material developed by the corporation. They shall also be invited to marketing events.

4.3 The Corporation shall display on approach road to the unit at 1000/500/100 meter distances the signage about the unit with the standard branding. The maintenance of these information displays shall be the duty of that particular unit.

4.4 The Corporation shall ensure that infrastructure is made and the unit is run as per the standards and norms fixed for it and the continuous breach shall call for an action according to lease agreement.

4.5 The Corporation shall provide necessary help and guidance for proper operation of unit and shall also provide skill development training, as and when required.

4.6 The Corporation shall have the right to draft and decide necessary proformas for application, check-list, inspection-report, compliance-report and other necessary proformas needed for construction, running, managing and granting franchisee for WSAs. Corporation shall also have the right to enforce these.

4.7 The Corporation shall have the right and execute, lease, licence, tender, format, RFP and other documents as per provisions of this policy.

4.8 The Corporation shall, as per provisions of policy, have the right to receive premium, lease rent, license fee, franchisee fee, registration fee and other amounts and deposit them in the account of the Corporation. The Corporation shall also have right to spend for development and management of WSAs and other local tourist facilities developed by the tourism department as per guidelines.

4.9 The Corporation shall have right to such administrative powers as are deemed to be necessary under the provisions of policy for development, running, managing, maintenance and regularization by Managing Director of the corporation.

5. DUTIES AND POWERS OF FRANCHISEE

5.1 The construction and running / managing of infrastructure shall be carried out as per standards and norms fixed by the Corporation and suggestions/guidance of the Corporation shall be followed.

5.2 All the amounts payble to Corporation shall be paid on time fixed for it.

5.3 All the permissions/registration/licenses shall be applied for & obtained for construction of infrastructure and carrying on the activities/business.

5.4 There shall always be friendly and cordial behaviour with tourists and travellers and top priority shall be given to their safety.

5.5 Arrangements for receiving complaints and immediately resolving them shall be made. Such arrangements shall be prominently displayed at the unit.

5.6 It shall be ensured that conditions laid down in the lease agreement, franchisee agreement etc executed with the corporation are strictly followed and carried out.

5.7 The unit shall have right to use logo, designs and other publicity material decided by Corporation for it's marketing and no other logo designs etc. shall be used by the unit.

5.8 The unit shall be able to use expertise of Corporation in construction, maintenance and opertion of the WSA in this connection.

6. MISCELLANEOUS

6.1 Managing Director of the Corporation shall be authorized for the implementation of the policy.

6.2 The amount of premium and lease rent received for the land leased out under the provisions of this policy shall be deposited with the Corporation and the Corporation shall have powers to spend it for the purpose of developing and maintaining WSAs and other local facilities for travellers as per guidelines issued by the Tourism Department.

6.3 Principal Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Department of Tourism shall be the authority to hear and decide any dispute arising between the Corporation, the unit/operation/franchisee or between any two of them regarding running, maintenance, management and regularization of WSAs. The decision of Principal Secretary shall be final and binding.

6.4 Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh shall be authorized to approve the draft of the tender documents, lease agreements and franchisee agreements.

6.5 A committee constituted under the Chairmanship of the Chief Secretary shall be empowered for elaborating, giving guidance, clarifying and amending this policy.

Note: For any clarification notified hindi version of this policy shall be refered.

M.P.
TOURISM
Coca-Cola
M.P.
TOURISM
Coca-Cola

The heart of Incredible India

Lease Agreement (Brown Field Model)

Way Side Amenities Given for Operation on Lease to Private Investor

Lease Agreement (Brown Field Model) Way Side Amenities Given for Operation on Lease to Private Investor

This agreement is made on ....day of ....year............ between the Governor of Madhya Pradesh, acting through.................., MP State Tourism Development Corporation (hereinafter called as the 'Lessor' which expression shall, where the context so permits, include its successor in office.) of the First Part

AND

M/s................................. (Address) through its Managing Director/ Partner/ Secretary Shri/Smt.....................................S/o/D/o/W/o..........................and having its registered office at.......................... (herein after called as the 'Lessee' which expression shall, where the context so permits, include its successors and permitted assigns) of the Second Part.

The Lessor and Lessee shall individually be referred to as 'Party' and collectively be referred to as 'Parties'.

WHEREAS the State Government of Madhya Pradesh has prepared the MP State Tourism Policy 2010 (as amended in 2014) whereby the State has set the goal to provide a comprehensive tourism experience

AND WHEREAS it has been observed that large number of people use the national/ state highways/ rural roads constructed within the State and thus there is requirement of providing facilities such as restaurants, toilets, petrol pumps etc. to ease the journey of people travelling on these roads.

AND WHEREAS the MP State Tourism Development Corporation keeping in mind the need to provide amenities on the road network located within the State has decided to establish way side amenities and has prepared a master plan.

AND WHEREAS the Lessor has invited applications for establishing/ operating the way side amenities established/ to be established/ to be operating by the Lessee and the Lessee has submitted its bid and has been selected to establish/ run/ operate the way side amenity located at .... comprising of an area admeasuring...................................situated in the village/ city of ....district......................, more particularly described in the Schedule on the terms and conditions set forth herein.

Now therefore, the Parties have agreed to as follows –

1. **Term of the Lease**

In consideration of the premium and lease rent and the terms and conditions of this lease agreement, the lessor shall demise to the lessee and the lessee shall accept a lease over the land (including all structures existing thereon), as more particularly specified in the Schedule for a period of THIRTY YEARS commencing from the date of entering into this agreement.

2. **Lease Rent/ Premium etc.**

The Lessee shall pay the following amount through bank draft to the Lessor for the said land –

i. Premium of ₹. .... (In words.........................).

ii. Annual Lease Rent, 1% of the upfront premium plus taxes as applicable.

iii. Bank Guarantee: Irrevocable and unconditional Bank Guarantee of INR 10.00 Lakh. Bank Guarantee shall be valid initially for 1 (one) year and thereafter kept valid & effective during the Lease Period by renewing its validity three (3) months prior to its expiry. Bank Guarantee shall be refurbished every year. (The Bank Guarantee should be issued from Nationalized Bank or Scheduled Bank).

iv. The first payment of such annual lease rent will fall due on the date of signing of lease agreement. Thereafter, the payment of annual lease rent shall be due and payable during the lease period by the lessee to the Authority on 1st April every year, the anniversary of the date of signing lease agreement. Failure to pay the annual lease rental upto 30th April every year will attract simple interest at the rate of 10% (ten percent) per annum for the delayed period.

3. **Facilities/ amenities to be developed/ provided by the Lessee**

3.1 The Lessee shall mandatorily provide, operate and maintain the following amenities –

(a) Parking for cars/tourist coach/bus/ motorcycle etc;

(b) Food Plaza/ Restaurant;

(c) Separate toilets and washrooms for men, women & handicaps disable including changing rooms;

(d) First Aid;

(e) 24 x 7 Water and electricity facility.

(f) Disposal of waste.

3.2 The lessee may establish/run/ operate/provide the following amenities after informing the Lessor in writing –

(a) Children's play area;

(b) Telephone/ internet kiosk;

(c) Souvenir/ handicrafts shop;

(d) Baby/ handicap care room;

(e) Fast food outlet/ Ice cream parlour;

(f) Mini general store;

(g) Vehicle repair shop/ car washing facility;

(h) Travel desk;

(i) Flower shop/ books-newspaper outlet;

(j) Live art/ handicraft display;

(k) Any other amenity which may be permitted by the Managing Director of the Lessor.

3.3 The Lessor may establish/run/ operate/provide the following amenities only after obtaining the consent of the Lessor in writing –

(a) Petrol Pump;

(b) Marriage Garden;

(c) Residential rooms;

(d) Bank ATM;

(e) Any other amenity which may be permitted by the Managing Director of the Lessor.

4. Powers and duties of the Lessor

4.1 The Lessor shall provide experts for assisting in branding provide advertisement material and approved designs to the Lessee for publicity.

4.2 The Lessor shall prepare material for publicity and spreading information about the way side amenity and boards/display/hoardings shall be placed on roads and information about the way side amenities shall be provided at functions organized by the Lessor.

4.3 The lessor shall initially place boards/ display/ hoardings informing about the way side amenity at 1000/500/100 m on both sides of the way side amenity. However, maintenance of the displays shall be the responsibility of the Lessee.

4.4 The lessor shall ensure that the Lessee has established the infrastructure and is operating the way side amenity as per the prescribed criteria. In case, the Lessee does not create the infrastructure or operates the way side amenity in violation or contravention of the prescribed criteria, appropriate action would be taken against the Lessee.

4.5 The lessor may provide support and guidance for good management of the amenity and if required provide necessary training for skill development.

4.6 The lessor shall have the right and power to determine and prescribe the manner and contents of the application form, check list, inspection report, compliance report, operational manual and other formats that may be necessary.

4.7 The Managing Director of the Lessor may as per administrative exigencies specify additional conditions.

5. Powers and duties of the Lessee

5.1 The lessee shall create and operate/ or operate the way side amenity as per the prescribed guidelines determined by the MP State Tourism Development Corporation.

5.2 The lessee shall ensure that all dues are paid as per the payment schedule prescribed by the Lessor.

5.3 The lessee shall maintain and use all structures which are located on the land leased to it. To provide services as per clause 3.1 of this agreement. The lessee may also create fresh infrastructure as per need according to the clause 3.2 & 3.3 of this agreement.

5.4 The lessee shall be responsible for obtaining all necessary permission /registrations/licenses for construction of infrastructure and activities provided.

5.5 The Lessee shall ensure that its / his staffs maintain friendly behaviour with travellers and tourists and their security shall be of utmost importance.

5.6 The Lessee shall ensure that there is an arrangement to hear and redress the grievances/ complaints of the tourists/ travellers and the process shall be advertised at the site.

5.7 The Lessee shall ensure compliance of all terms and conditions mentioned in the lease Agreement, entered into with the Lessor and the instruction given by the lessor from time to time.

5.8 The Lessee shall use the services of the persons appointed by the Lessor and use the designs and publicity material provided by the Lessor for marketing of the way side amenity, apart from this, no other person or design etc. will be used by the Lessee.

5.9 The Lessee may use the benefit of the Lessor's expertise in construction, maintenance and management of the site.

6. General Conditions of Lease

6.1 The Lessee shall be liable to pay the annual lease rent on 1st April of each year. The annual lease rent must be paid by 30th April of each year otherwise, the same would be payable along with 10% simple interest per annum.

6.2 If the Lessee fails to pay the annual lease rent for 06 months from the due date, then the Lessor shall be at liberty to terminate the lease agreement. However, if the Lessee pays the due amount along with interest in lump sum manner, the authorised officer of the Lessor shall renew the lease agreement after taking 10% of the premium amount.

6.3 All sums, such as due amount of premium, lease rent or any other charges imposed by the lessor may be recovered as an arrears of land revenue, if the same is not paid before the due date.

6.4 If the lessee is a body corporate/ company then the promoter(s) of the body corporate/ company who holds atleast 51% of the shareholding in the body corporate/ company at the time of executing this agreement shall not dilute his/its shareholding to less than 51% for a period of 3 years from the date of starting operation of the WSA. However, the lessee may dilute/ change/ amend its remaining shareholding pattern.

The promoter holding 51% of the shareholding in the body corporate may dilute its shareholding after 3 years of starting operation of the WSA with the permission of the lessor. However, the name, registered office, business purpose shall not be altered during the validity of the lease period.

6.5 A proprietary firm may also be allowed to add partner, change constitution/ownership after three years from the date of starting operation with the permission of lessor.

6.6 The lessee shall not undertake any construction work at the site without obtaining the necessary permissions/ approvals/ licenses from the competent authority or from the lessor under clause 3.3 hereinabove. The lessee shall not undertake any construction activity without obtaining necessary approvals of maps by the competent authority.

6.7 The lessee shall not raise any construction in contravention to the provisions of this agreement. The lessee shall not use the site for any purpose not mentioned in this lease agreement.

6.8 The lessee shall ensure that all activities are completed within the stipulated time period as may be prescribed by the lessor. If the lessee fails to implement the project to the satisfaction of the lessor, the lease agreement is liable to be terminated.

6.9 The lessee shall ensure that the site is continuously used for the purpose this lease is being granted. If, for a period of one year, the lessee fails to operate the land for the purpose of this lease or if the site is shut for a period of one year, then the lessor shall terminate the lease.

6.10 If the lessee uses the site for any other purpose than the one mentioned in this lease, the lease shall be terminated by the lessor.

6.11 The lessee shall be responsible for the safety and security of the way side amenity and shall be responsible for the upkeep and maintenance of the amenities at its own cost. The lessee shall also ensure that no cars are parked on the road and proper parking arrangements are provided within the site.

6.12 The lessee shall be responsible for maintaining adequate insurance cover for the way side amenity and shall keep all receipts of insurance paid safely and will be obligated to provide it to the lessor upon demand.

6.13 The lessee shall be responsible for protection of the environment at the site. The lessee shall not undertake any activity that causes harm to the environment. Further, atleast 10 percent of the land must be brought under green cover.

6.14 Upon cancellation/ termination of lease agreement or completion of lease period, the lessor shall have right to enter and take possession of the site and re-allot/ tender the site. All fixed capital assets at the site (whether developed by the lessee or not) shall be peacefully handed over to the lessor upon cancellation/ termination of lease agreement or upon completion of lease period. It is clarified that the lessee shall not be entitled for receiving any payment from the lessor or any third person for the infrastructure constructed and maintained. However the lease renewal may be considered by the MD – MPSTDC as per then prevailing rules/ policy.

6.15 Fixed capital assets for the purpose of this agreement shall mean all construction created on the land, water and electrical supply system with fixture, air conditioning system, water purification system, gas pipeline, parking and stares, entry gate, fencing boundary wall, well, tube well, water storage tank.

6.16 The lessee shall ensure compliance of all rules/ regulations made by any department of the State Government, related to running of activities in WSA.

6.17 The lessee shall be responsible for any damage or loss caused at the site and if any loss or damage is caused to any person due to the activities of the lessee, the same shall be the responsibility and shall be borne by the lessee.

6.18 The lessee upon registration of this lease agreement shall deposit the certified copy of the registered lease agreement with the authorised officer of the lessor and keep the original with itself/ himself.

6.19 The lessee shall pay ₹1000 for any amendment of the lease agreement where no fees or premium has been specified.

6.20 The lessee shall from time to time and at all times during the term of the lease pay all taxes, rates, assessments and other charges which are charged, imposed or assessed on the said land.

6.21 The lessee shall not carry on any illegal trade or business on the said premises.

6.22 The lessee shall not sell, transfer, grant lease or otherwise dispose of any asset located at the site without the prior written permission of the lessor. The lessee shall not sub-lease any portion of the land specified in schedule, including the buildings constructed thereon.

6.23 The lessee shall abide and comply with the Operation Manual and Way Side Amenities (establishment and management) Policy 2016 of the Tourism Department, State of MP as specified in Schedule –I and II herein.

6.24 The RFP/ Tender document shall be treated to be a part of this agreement. Any condition specified therein and not mentioned here shall also be binding on the parties. However, if there is any conflict between the provisions of the RFP/ tender and this lease agreement, then the provisions of this lease agreement would prevail.

7. Event of Default

7.1 In the event of any breach in term & condition of lease the MPSTDC would have the right to impose penalty upto 10% of the premium amount, without prejudice to the right of MPSTDC to take other action including termination.

7.2 Unless expressly provided otherwise herein, if the lessee has defaulted in performance of any term or condition mentioned herein and such default has continued for a period of 30 days after notice in writing thereof has been given to the lessee by the lessor, the lessor shall terminate/ cancel the lease agreement.

8. Termination of lease Agreement

Either party may terminate this lease agreement by giving 3 months prior written notice to the other party. Upon termination of lease agreement, the lessor shall have right to enter and take possession of the site and re-allot/ tender the site. All fixed capital assets and infrastructure at the site (whether developed by the lessee or not) shall be peacefully handed over to the lessor upon termination of lease agreement. It is clarified that the lessee shall not be entitled for receiving any payment from the lessor or any third person for the fixed capital assets infrastructure constructed and maintained.

9. Assignment

The lessee may with the prior permission of the lessor assign or authorise any person to operate a specific amenity within the site. However, the lessee shall be responsible for the conduct and behaviour of the assignee and shall ensure that the assignee complies with all terms and conditions mentioned herein.

10. Dispute Resolution

10.1 In case of any dispute (except for cancellation of lease agreement) the parties will attempt in good faith to resolve any dispute initially through negotiations between the parties. If the dispute cannot be settled amicably within 14 days from the date on which either party has served written notice on the other of the dispute then the dispute shall be resolved as per clause 10.2.

10.2 In the event of a dispute between the parties which could not be amicable resolved. The aggrieved party shall refer the dispute to be resolved by arbitration.

The arbitral proceedings shall be presided by a single arbitrator who shall be the Principal Secretary/ Secretary of the Tourism Department, Government of Madhya Pradesh.

10.3 If the lessor terminates/ cancels the lease agreement, the lessee may within 30 days from the date of issuance of termination/ cancellation order, prefer an appeal before the Secretary Department of Tourism Government of Madhya Pradesh challenging the termination/ cancellation order. The decision passed by the Secretary shall be final and binding on both parties. If no appeal is preferred within 30 days of issuance of termination/ cancellation order, the right of the lessee to challenge the termination/ cancellation order shall be closed.

10.4 If the lessee files an appeal as per clause 10.3, the Secretary shall after granting an opportunity of hearing to the lessee be competent to pass any orders that may be deemed necessary.

10.5 If the Secretary rejects/ dismisses the appeal filed by the lessee, the lessee shall peacefully hand over the property mentioned in Schedule to the lessor and remove all its/ his /her staff and employees within 10 days from issuance of rejection/ dismissal order.

10.6 The sitting of all challenges arising out of the agreement or its implementation shall be in Bhopal. The District court of Bhopal and High Court of Madhya Pradesh Principal seat at Jabalpur shall have Jurisdiction over matters arising out of arbitration.

11. Governing Law

This agreement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of India.

Schedule

Description of the properties under this lease agreement is as under.

1. Land-

Patwari Halka No.- …………………………………….

Khasra No. - ……………………………………………

Village- …………………………………………………

Tehsil- ………………………………………………….

District- …………………………………………………

Area (Rakba) in Hect.- ………………………………

2. Boundaries of the land

In the East- …………………………………………….

In the West- ……………………………………………

In the North- …………………………………………

In the South- …………………………………………

3. Construction under the land in square feet

Restaurant- ……………………………………………

Kitchen- …………………………………………………

Toilets- …………………………………………………

Manager room- ………………………………………

Store- ……………………………………………………

Corridor- ………………………………………………….....

Rooms- …………………………………………………….....

Other constructions- ……………………………….....

Total area- ………………………………………….......

4. **Khasra Map, Nakal and Station survey map of the land allotted above duly signed by both the parties.**

IN WITNESS WHEREOF, the Parties herein above have set their hands entered into this Agreement the day and year first above written.

Witness	For Lessor, MP State Tourism Development Corporation Limited through ………………………………………....... For lessee M/S ……………………………................... ……………….............through…………………….......

The heart of
Incredible !ndia

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित

मिडवे ट्रीट संचालन निर्देशिका

मिडवे ट्रीट संचालन निर्देशिका

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लीज पर दी गई मिडवे ट्रीट (WSA) के सुचारू संचालन एवं नियंत्रण हेतु मार्गदर्शिका में उल्लेखित नियमों का पालन अति आवश्यक है।

1. स्वागत कक्ष

1. स्वागत कक्ष में आने वाले प्रत्येक अतिथियों का अभिनंदन/अभिवादन करें।
2. महिलाओं से संबंधित अपराध की रोकथाम के लिये पुलिस हेल्प लाइन का नंबर 1090 एवं पर्यटकों को पर्यटन संबंधी जानकारी के लिये टोल फ्री नंबर 1800 233 7777 की जानकारी स्वागत कक्ष पर प्रदर्शित करें। साथ ही पर्यटकों को जानकारी दें।
3. स्वागत कक्ष में उपलब्ध टेलीफोन तत्काल अटेंड किया जाये।
4. इकाई के स्वागत कक्ष पर मध्यप्रदेश पर्यटन का ब्रोशर नि:शुल्क उपलब्ध हो।
5. इकाई में फर्स्ट एड बॉक्स आवश्यकतानुसार उपलब्ध होना चाहिये।
6. स्वागत कक्ष पर होटल के आस-पास उपलब्ध शहर के अच्छे डॉक्टरों के टेलीफोन नंबर उपलब्ध हों।

2. कैफेटेरिया

1. सभी कर्मचारी निर्धारित यूनिफार्म में हों, उनकी शेव बनी हुई हो, जूते पॉलिश किये हुये हों तथा नाखून कटे हुये हों। जो भी कर्मचारी खान-पान हेन्डिल करते हैं उनके नाखून तथा बाल कटे होने चाहिये। पकाने वाले/सर्विस करने वाले हैंड ग्लब्ज पहनकर सर्विस करें। साफ-सुथरा दिखना चाहिये।
2. गेस्ट हमेशा सही है, उससे बहस नहीं करना चाहिये। किसी भी अतिथि को उंगली दिखाकर किसी भी तरीके का इशारा न करें।
3. चटके हुए एवं दाग लगे हुए ग्लास, प्लेट तथा कप इत्यादि का उपयोग न करें।
4. बना हुआ खाना सर्विस ट्रे तथा क्राकरी/कटलरी को फर्श पर न रखा जाये।
5. पैक भोजन में चम्मच, पेपर नेपकिन तथा आवश्यकतानुसार नमक, मिर्ची, सॉस तथा अचार के सेशे रखे जाने चाहिए।
6. इकाइयों में सभी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक जैसे - पेप्सी, कोक, लिम्का, सोडा, फ्रूटी, मिनरल वाटर एवं आईसक्रीम आदि विशेष ब्राण्ड की ही क्रय की जाये। फ्रूटी, मिनरल वाटर आदि खरीदते समय उसके निर्माण की तिथि अवश्य देखी जावे तथा फ्रिज में रखने के पूर्व साफ कर ली जाये।
7. इकाइयों तथा रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक्स/सॉफ्ट ड्रिंक्स को गिलास में तथा वेफर्स/चिप्स/ अन्य कई पैकेट्स में बंद वस्तुओं को प्लेट में डालकर सर्व किया जाये।

3. किचन

1. किचन के टाईल्स एवं फर्श की साफ–सफाई नियमित रूप से की जाये।
2. किचन में सामग्री आवश्यकतानुसार ही रखी जाये तथा शेष सामग्री स्टोर में रखी जाये।
3. गैस पाईपलाइन के ऊपर लाल रंग का पेंट करवाया जाये तथा लीकेज को बराबर चैक करते रहें। गैस बैंक की चैकिंग नियमित की जाये। गैस बर्नर्स की रोज सफाई की जाये।
4. किचन में स्टेनलैस स्टील के चाकू–छुरियों का ही उपयोग किया जाये।
5. किचन में साग–सब्जी का धोकर उपयोग किया जाये एवं पॉलिथिन अथवा पुराने अखबारों का उपयोग ना किया जाये।
6. खाद्य सामग्री एवं आवश्यक सब्जी निर्धारित स्थान पर रखी जाये।
7. किचन के स्टोर में रखी गई सामग्री के डिब्बों पर सामग्री का नाम अंकित किया जाये।
8. कुकिंग रेंज, सिंक, टेबल टॉप एवं यूटेन्सिल्स आदि को सोप सोल्युशन से धुलवाकर एवं सुखाकर रखा जाये।
9. किचन में नियमित रूप से पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट करवाया जाये।
10. सभी पकी हुई खाद्य सामग्री एल्युमीनियम फाइल अथवा ढक्कन से ढकी हुई रखना चाहिये।
11. शाकाहारी, मांसाहारी एवं फिश के लिये चॉपिंग बोर्ड हरे, लाल, सफेद होने चाहिये एवं स्थान अलग–अलग हों। काटने के चाकू भी तीन प्रकार के हों।
12. डेयरी पदार्थ शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य सामग्री रखने के लिये डीप फ्रिज/फ्रिज अलग होने चाहिये।
13. वेट गार्वेज पिट अच्छी तरह से ढंका हो, उसमें पॉलिथिन/प्लास्टिक ना डाला जाये।
14. खाद्य सामग्री/टिंड प्रोडक्ट उत्तम स्तर के ही क्रय किये जाये।
15. कुक/हेल्पर पूर्ण वर्दी, एप्रेन एवं शेफ कैप पहनकर ही काम करें।
16. किचन में इस्तेमाल होने वाले डस्टर साफ–सुथरे हों।
17. जो भी कर्मचारी खान–पान हेन्डिल करते हैं उनके नाखून तथा बाल कटे होने चाहिए। पकाने वाले/सर्विस करने वाले हैंड ग्लब्ज पहनकर सर्विस करें।
18. मटन, चिकन, फिश, क्रीम, पनीर आदि उच्च स्तर का ही खरीदा जाये।
19. बटर, चिकन, टोमेटो सूप अथवा बिरयानी आदि में रंग का उपयोग नहीं किया जाये।
20. ताजी सब्जियाँ, ताजे फल, ताजी ब्रेड, ताजा पनीर, ताजी क्रीम, ताजा दूध, अण्डे आदि सामग्री के नियमित उपलब्धता की व्यवस्था की जाये।
21. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त खाद्य सामग्री इकाई पर उपलब्ध हो, उदाहरण के लिये मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, सोडा, समस्त प्रकार के जूसेस, फ्रूट कॉक्टेल, बटर, सफोला तेल, डबल रिफाईन्ड तेल, अच्छे स्तर का आटा, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, चीज, जैम, मॉमलेड, शहद, शुगर फ्री टेबलेट, कस्टर सुगर, शुगर क्यूब, टी बैग, अच्छी क्वालिटी का बेसन, मैदा, अरारोट, ग्रीन लेबल टी एवं रेड लेबल टी, नैस्कैफे, ग्राईंडेड कॉफी, स्ट्रा, व्हाइट पेपर, मस्टर्ड पावडर, कस्टर्ड पावडर, टमाटो सॉस, टमाटो कैचअप, टमाटो प्यूरी, चिली सॉस, टोबैस्को सॉस, वोस्टर सास, विनेगर एवं देशी घी इत्यादि।
22. किचन के दरवाजे अनावश्यक रूप से खुले नहीं रखे जायें तथा मक्खियों एवं मच्छरों से खाद्य सामग्री के बचाव पर विशेष ध्यान दिया जाये। दरवाजे तथा खिड़की पर जाली का प्रावधान हो।
23. बना हुआ खाना तथा क्राकरी/कटलरी को फर्श पर न रखा जाये।

24. कच्ची सामग्री जैसे चिकन/मटन/फिश/पनीर/सब्जी आदि पॉलिथिन में पैक कर फ्रीज/डीप फ्रिज में रखी जाये ताकि मांसाहारी खाद्य सामग्री एवं शाकाहारी खाद्य सामग्री आपस में मिक्स ना हो अथवा यदि उपलब्ध हो तो अलग-अलग फ्रिज/डीप फ्रिज में रखे।
25. किचन के पीछे नियमित सफाई रखें वहाँ पर खाली बोतलों व टीन के ढेर न रखे जायें।

4. हाउसकीपिंग/मेंटेनेंस

1. इकाई में पानी के टेप, डब्ल्यू.सी. सभी लाइट प्वाईट, फेन एवं एग्जास्ट फेन आदि चालू हालत में हो।
2. इकाइयों में पेस्ट कंट्रोल ट्रीटमेंट करवाया जाये।
3. किचन की सफाई, लॉबी की सफाई, पब्लिक टायलेट की सफाई एवं होटल के बाहरी प्रांगण, प्रवेश द्वार की सफाई पर ध्यान दिया जाये।
4. किसी भी इकाई में टूटी हुई कुर्सियाँ अथवा टूटा फर्नीचर न हो।
5. इकाईयों में एक्वागार्ड भलीभांति साफ करवाये जायें तथा ए.एम.सी. करायी जाये।
6. सभी इकाईयों में पानी की टंकियों को साफ करवा लिया जावे एवं वाटर फिल्टर आदि में यदि कैण्डिल बदलने की आवश्यकता हो तो उन्हें बदलवाया जाये। यदि कैण्डिल साफ करवाने की आवश्यकता हो तो उसे साफ करवाया जाये तथा ए.सी. के पैड साफ करवा लिये जाये। पानी की टंकी पर सफाई की तारीख अंकित की जाये।
7. वर्षा ऋतु के पहले सीवरेज टैंक अथवा नालियों एवं छत की सफाई करवायी जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि इकाई की छत पर कचरा अथवा टूटी-फूटी बोलतें न पड़ी हों।
8. रेफ्रिजरेटर तथा डीप फ्रीजर/वाटर कूलर/बॉटल कूलर भी प्रत्येक सप्ताह साफ करवाये जायें, जिससे कि उसमें काकरोच एवं कीड़े आदि न रहें।

5. लेखा

1. मैन्यु, बोर्ड पर मूल्य सहित प्रदर्शित किया जाये।
2. ग्राहकों से भुगतान उचित मूल्य पर प्राप्त किया जाये।
3. ग्राहकों को टिन तथा सर्विस टैक्स नंबर के साथ बिल प्रदाय किया जाये।
4. इकाई के चालन हेतु सभी आवश्यक लायसेंस संबंधित विभाग से प्राप्त किये जायें तथा उनकी प्रति पर्यटन विकास निगम को प्रेषित की जाये।
5. समस्त लायसेंसों का समयावधि में नवीनीकरण किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा नवीनीकृत लायसेंसों की प्रति भी पर्यटन विकास निगम को प्रेषित की जाये।
6. इकाई में नियमानुसार लगने वाले टैक्स हेतु संबंधित विभागों/संस्थाओं से पंजीकरण करवाया जाये।
7. सभी टैक्स संबंधित विभागों में समय पर भुगतान किया जाये एवं संबंधित विभागों में समयावधि में रिटर्न जमा कर एक प्रति मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम में प्रेषित की जाये।
8. सभी करों के भुगतान के प्रतिवेदन की प्रति मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. इकाई के सभी लायसेंस की प्रति फ्रेम बनवाकर कार्यालय में प्रदर्शित की जाये।

6. स्टोर

1. समस्त खाद्य सामग्री पर लेबिल लगाकर रखा जाये।
2. खाद्य सामग्री के लिये स्टील के टिन/बर्तन रखे जाये।
3. खाद्य सामग्री के स्टोर में किसी भी प्रकार की चूहेमार अथवा अन्य दवाई ना रखी जाये।
4. पैकिंग तारीख देख कर ही डिब्बा बंद सामग्री क्रय की जाये तथा जो सामग्री पहले खरीदी है को आगे रखे और जो बाद में खरीदी है उसे पीछे रखे।
5. एक्सपायरी डेट की सामग्री को अलग रखे तथा नियमित रूप से नष्ट किया जाए।

7. विविध

1. इकाइयों में अग्निशामक यंत्र अनिवार्य होना चाहिये। अग्निशामक यंत्र का समय–समय पर रख–रखाव, रिफिल कराया जाना आवश्यक है तथा रिफिलिंग की तारीख अंकित की जाये।
2. समस्त इकाइयों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के परिचय–पत्र अनिवार्य रूप से बनवाये जायें एवं समय–समय पर शासकीय डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए।
3. पानी की टंकी की सफाई समय अनुसार की जाए।
4. इकाईयों में गार्डन अम्ब्रेला लगवाया जाये।
5. धूम्रपान निषेध का पालन किया जाये।
6. गार्डनिंग तथा लॉन को मेन्टेन रखा जाये।
7. गार्बेज डिस्पोजल व्यवस्था होना आवश्यक है।
8. सम्पत्तियों के बीमा संबंधी कार्यवाही भी नियमानुसार प्रतिपादित की जाये तथा किसी भी नुकसान अथवा भरपाई के लिए तत्काल प्रकरण तैयार कर आवश्यक मुआवजा प्राप्त किया जाये।
9. इकाई के मूल रूप में उन्नयन, वृद्धि एवं नवीनीकरण के पूर्व मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा।
10. इकाई के मूल स्वरूप (Site Plan) में किए गए उन्नयन वृद्धि तथा नवीनीकरण से संबंधित स्वीकृति की जानकारी।
11. नि:शक्तजनों/बुजुर्गो हेतु रेंप, शौचालय आदि सुविधाएँ पृथक से रखी जाये।
12. निगम द्वारा समय–समय पर रख–रखाव एवं संचालन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
13. निगम द्वारा निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के समय सहयोग दिया जाये एवं जानकारी उपलब्ध कराई जाये।

8. इकाई प्रभारी/मालिक द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले जाँच/कार्यो की सूची

1. किचन/रेस्टोरेंट/बार एवं वांशिंग ऐरिये का निरीक्षण कर बेहतर स्तर की सफाई सुनिश्चित करना।
2. कर्मचारी यूनिफार्म में है यह सुनिश्चित करना एवं समय–समय पर अलग–अलग विभाग के कर्मचारियों का ब्रीफिंग सुनिश्चित करना।
3. कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता को सुनिश्चित करना।
4. अधिक से अधिक पर्यटक/अतिथियों से संपर्क करना।
5. इकाई में लगा हुआ किचन/रेस्टोरेट एवं विद्युत उपकरण चालू हालत में है यह सुनिश्चित करना।
6. लॉन एवं पेड़–पौधों की समुचित देख–रेख सुनिश्चित करना।
7. पार्किंग एरिया तथा पब्लिक टॉयलेट की साफ–सफाई चैक करना।

9. क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा त्रैमासिक किया जावे वाला निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	इकाई का नाम	
2.	इकाई के निरीक्षण का दिनांक	
3.	इकाई के प्रभारी/मालिक का नाम	
4.	इकाई में पदस्थ स्टाफ की कुल संख्या	
5.	स्टाफ यूनिफार्म की स्थिति	
6.	इकाई के साफ–सफाई की स्थिति (i) स्वागत कक्ष (ii) रेस्टोरेन्ट (iii) किचन (iv) खाने की सामग्री का स्टोर (v) पार्किंग एरिया (vi) गार्डन (vii) लेडीज एवं जेन्टस टॉयलेट	
7.	विशेष (i) इकाई संचालन हेतु उपलब्ध लाईसेंस/अनुमतियों की वैधता (ii) इकाई द्वारा जमा किये गये करों की जानकारी (iii) इकाई के मूल स्वरूप (Site Plan) में किये गये उन्नयन वृद्धि तथा नवीनीकरण से संबंधित स्वीकृति की जानकारी	
8.	इकाई के संचालन का स्तर (i) उत्तम (ii) संतोषजनक (iii) असंतोषजनक	
9.	इकाई संचालन में कमियां तथा सुझाव	

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
पद एवं पदस्थापना

The heart of Incredible India

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित

(निवेश संवर्धन एवं योजना प्रभाग)

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल–462003 | टेली.: 0755–4027168, 4027180

ईमेलः **dirtpu@mptourism.com** | वेबसाईटः **www.mpstdc.com**

Aquarius